उच्च शिक्षा में गुणात्मक ह्रास एवं बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी

डॉ0 अवध बिहारी सिंह*

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के व्यवहार में इच्छित सकारात्मक बदलाव लाती है। प्रभावी शिक्षा व्यक्ति के प्रवृत्ति कौशल ज्ञान एवं सोच में परिवर्तन लाने में सहायक है। मनुष्य के शारीरिक मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक स्तर पर विकास में शिक्षा की महती भूमिका है। शिक्षा हर तरह के अपेक्षित बदलाव एवं सुधार की धुरी होती है। किसी भी विकासशील समाज की शिक्षा रीढ़ होने के साथ ही उसके उत्थान एवं परिपक्वता का दर्पण होता है। शिक्षा से वंचित कोई भी व्यक्ति या समाज कभी भी अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं कर पाता है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र में प्रर्याप्त मात्रा में ऐसा मानव संसाधन उपलब्ध हो जो राष्ट्र के प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का समुचित सदुपयोग कर सके। मानव संसाधनों के विकास में सर्वप्रथम स्थान शिक्षा का है। उच्च शिक्षा किसी भी देश की प्रगति का मूल आधार होती है। उच्च शिक्षा द्वारा देश के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक विकास का आधार बिन्दु निर्धारित होता है। जिसका उद्देश्य मानवता, सहनशीलता, दूरदर्शिता तर्कपूर्ण विचारों का विकास, विभिन्न व्यवसायों का उत्कष्ट प्रशिक्षण तथा सत्य की खोज करना। वस्तुतः एक सुसंस्कृत एवं उन्नतिशील समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में उच्च शिक्षा की महती भूमिका होती है।

सामान्यतः सबको प्रदान की जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में दी जाने वाली विशेष शिक्षा को उच्च शिक्षा कहा जाता है यह शिक्षा विश्वविद्यालयों,महाविद्यालयों,प्रौद्योगिकी संस्थानों में दी जाती है। प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है। यह ऐच्छिक होता है। इसके तहत स्नातक,स्नातकोत्तर, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते हैं। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। उच्च शिक्षा के निमित्त स्थापित विश्वविद्यालय के दायित्वों के विषय में डॉ0 राधाकृष्णन का यह कथन प्रासंगिक है।–''The function of the university is not merel to send out Technically skilled and professionally competent men, but it is their duty to produce in them the quality which enables the individuals to treat one another in a truly democratic spirit"[1].

***प्रवक्ता, जनसंचार विभाग, वी0बी0एस0 पूर्वांचल वि0वि0, जौनपुर।**

वहीं शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में यूनेस्को का कथन है कि–''शिक्षा दृष्टिकोण विस्तृत करने और कौशल बढ़ाने की वह सुनियोजित प्रक्रिया है जो स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी है। सामाजिक परिर्वतन और आर्थिक तथा राजनीतिक बदलाव सभी देशों के लिए और खासतौर से उन विकासशील देशों के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी जनता के हर वर्ग की मूल आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आमूल–चूल परिवर्तन लाने को प्रयत्नशील हैं।–''[2]

यूपीए सरकार में शिक्षा बचाओ आन्दोलन समिति के संयुक्त सचिव तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव श्री अतुल कोठारी के अनुसार सन् 1947 में भारत में 18 विश्वविद्यालय, 518 महाविद्यालय, 24,000 शिक्षक तथा 2,28,881 छात्र थे। वहीं सन् 2009 में 504 विश्वविद्यालय, 25,951 महाविद्यालय, 5,85,000 शिक्षक तथा 136.42 लाख छात्र थे। विकीपीडिया के अनुसार भारत में पिछले पचास वर्षों में विश्वविद्यालयों की संख्या में 11.6 गुना, महाविद्यालयों की संख्या में 12.5 गुना,विद्यार्थियों की संख्या में 60 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 25 गुना वृद्धि हुई है। इस तरह से सबको उच्च शिक्षा प्रदान करने की नीति के तहत भारत में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस समय 45 केन्द्रीय, 322 राज्य, 128 डीम्ड तथा 192 निजी विश्वविद्यालय हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 62 विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है।

भारत में आजादी से पहले मानवीय मूल्यों की स्थापना, संस्कृति एवं सभ्यता के विकास और युवाओं के स्वावलम्बन हेतु मिशनरी भावना से प्रेरित होकर देशभक्तों महापुरूषों समाज सेवीयों द्वारा भिक्षाटन करके तथा दान मांग कर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना जैसा पुनीत कार्य किया जाता था। उनका यह कार्य समाज एवं राष्ट्र के उन्नयन भाव से प्रेरित होता था। इस सन्दर्भ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के संस्थापक भारत रत्न पं0 मदन मोहन मालवीय जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। देश के युवाओं को स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें विभिन्न कलाओं तथा विज्ञानों की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मालवीय जी की निष्ठा एवं उनके अध्यवसाय की प्रशंसा करते हुए डॉ0 एनी बेसेन्ट ने कहा था कि ''मालवीय जी ने अपना समस्त सांसारिक जीवन, अपनी शक्ति, अपनी प्रबल भाषण कला, यहाँ तक कि स्वयं अपने को और अपने स्वास्थ्य को इस महान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए बलिदान कर दिया है।"[3]

आजादी के कुछ वर्षों बाद शिक्षा का व्यावसायीकरण शुरू हो गया। यह मुनाफा कमाने का एक अच्छा माध्यम लोगों को नजर आने लगा। पिछले दो दशकों से तो यह कालेधन को सफेद करने का सबसे अच्छा साधन होता जा रहा है। अधिकांश मंत्री, सांसद, विधायक, उद्योगपति, ठेकेदार, माफिया, भट्ठा मालिक, भ्रष्ट अधिकारी स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग संस्थान, एम.बी.ए., बी.फार्मा, स्कूल तथा मेडिकल कालेज खोलना शुरू कर दिए हैं। सरकारी तंत्र में अपने रसूख तथा पैसा के बल पर बिना मानक पूर्ण किये हुए आसानी से उच्च शिक्षण संस्थायें खोलते जा रहे हैं। शैक्षणिक, छात्रावास तथा प्रायोगिक शुल्क के नाम पर मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। वहीं स्ववित्तपोषित योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों का लगातार शोषण किया जा रहा है। सरकारी/अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों/प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया में पैसा एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लाखों का चढ़ावा चढ़ाकर चयनित शिक्षकों/प्राचार्यों से कतर्व्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने की आशा भी बेमानी है। अनुदानित कालेजों के प्रबन्ध तंत्र पर ऐसे लोगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है जिनका शिक्षा से कोई नाता नहीं है। ऐसे लोग महाविद्यालयों को अपने ऐशो–आराम तथा धन उगाही का केन्द्र बनाते जा रहे हैं। अब तो विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी लोगों की उंगली उठने लगी हैं।

देश की शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए विशेष गुप्ता ने लिखा है कि ''देश के कुछेक संस्थाओं को छोड़कर अधिकांश संस्थाएं छात्रों को प्रवेश परीक्षा और डिग्री बाँटने तक ही सीमित हैं। देश में लगभग 700 विश्वविद्यालय है और इनसे जुड़े लगभग 36 हजार महाविद्यालय हैं जिनमें तीन करोड़ से अधिक छात्रों का नामांकन है। मानव संसाधन मंत्रालय के ताजे आकड़ो से पता चलता है कि देश के आईआईटी,आईआईएम,एनआईटी,आईएमसी जैसे संस्थान तकरीबन 35 प्रतिशत शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। आईआईटी में 29 प्रतिशत, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 38 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं। राज्य विश्वविद्यालयों की हालत और भी खस्ता है। यूजीसी ने स्नातकोत्तर स्तर पर जहाँ 12 छात्रों पर एक शिक्षक तथा स्नातक स्तर पर 15 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात निर्धारित किया है किन्तु वर्तमान में 23 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात है। सन 2030 तक उच्चशिक्षा में नामांकन प्रतिशत बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा तब उच्चशिक्षा की जरुरत को पूर्ण करने के लिए लगभग 800 विश्वविद्यालयों तथा 70 हजार महाविद्यालयों की जरुरत होगी। ..... विकसित देश जहाँ उच्चशिक्षा पर अपने कुल वजट का 9 फीसदी खर्च कर रहे हैं। वहीं भारत में राष्ट्रीय आय का एक फीसदी से भी कम उच्चशिक्षा पर खर्च किया जा रहा है।1964 में कोठारी

कमीशन ने शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत तथा भारतीय ज्ञान आयोग नें उच्चशिक्षा पर 1.5 फीसदी खर्च करने का सुझाव दिया था। इससे स्वतः स्पष्ट है कि हम उच्चशिक्षा के विकास के लिए विकसित देशों से कितने पीछे चल रहे हैं।

ब्रिक्स देशों में केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ शोध पर कुल जीडीपी का मात्र 0.9 फीसदी खर्च किया जाता है । वहीं चीन में 1.9 फीसदी, रुस में 1.5 फीसदी, ब्राजील में 1.3 फीसदी, दक्षिण अफ्रीका में 1 फीसदी धन खर्च किया जाता है। इसीलिए तो राष्ट्रीय उच्चशिक्षा मूल्यांकन परिषद ने अपनी रिर्पोट में स्पष्ट कहा है कि भारत के 68 प्रतिशत विश्वविद्यालयों और 90 प्रतिशत कॉलेजों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता मध्यम/दोयम दर्जे की या दोषपूर्ण है। इन संस्थानों के 75 प्रतिशत उतीर्ण छात्र आज बेरोजगार हैं..... पिछले दो दशकों में जिस तरह से देश की उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ है उससे अनेक उद्योगपति रातोरात शिक्षाविद बन उच्च शिक्षा को मुनाफा भरा कारोबार बना दिया जिससे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में लगातार गिरावट जारी है।''[4]

जब से केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों ने उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं बेरूखी दिखाना शुरू किया है तब से शिक्षा में हर स्तर पर लगातार गिरावट जारी है। इसके मूल कारण का जिक्र करते हुए एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जगमोहन राजपूत ने लिखा है कि ''शिक्षा के लिए जीडीपी के छह प्रतिशत आवंटन के वायदे अनेक दशकों से होते आ रहे हैं मगर यह चार प्रतिशत से कम ही रहता है। केन्द्र द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा अनेक अन्य महत्वपूर्ण संस्थान भी संसाधनों की कमी को ही शोध तथा नवाचार के लिए बड़ा अवरोध मानते हैं। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना कठिन नही है। केन्द्र सरकारों तथा राज्य सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता पर निगाह रखने के लिए जो संस्थायें बनाई है उनकी साख लगातार गिरती रही है।''[5]

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, अनुदानित महाविद्यालयों, तथा राजकीय महाविद्यालयों में विगत कुछ वर्षों से काफी तादात में शिक्षक सेवा निवृत्त हो रहें तथा कुछ पद पहले से ही खाली पड़े हैं जिन पर वर्षों से नई नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। जिसके चलते विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं। इससे उच्च शिक्षा का पठन–पाठन एवं शोध कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। इसके कारण छात्रों में असंतोष भी बढ़ रहा है। इससे सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों, कालेजों एवं संस्थानों में शिक्षक बनने से युवाओं का मोह भी भंग होता जा रहा है। इस सन्दर्भ में आनन्द कुमार ने लिखा है कि ''अगर हम यूजीसी के आकड़ों पर गौर करें तो विभिन्न महाविद्यालयों को सुचारू ढंग से

संचालित करने के लिए लगभग 14 लाख शिक्षकों की तत्काल जरूरत है। मानव संसाधन मंत्रालय के आकड़ों के अनुसार यूपी में तीन लाख, बिहार में 2.6 लाख और पश्चिम बंगाल में एक लाख स्कूली शिक्षकों की कमी है।"[6]

उच्च शिक्षा एवं शोध की लगातार गिरती गुणवत्ता के चलते भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है जिसके चलते बीटेक,एमटेक,एवं पीएचडी डिग्री धारक बेरोजगारों को उनकी डिग्री के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रही है जिसके चलते ''उत्तर प्रदेश में चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इन अर्जी देने वालों में 255 लोग पीएचडी हैं, कई बीटेक और एमटेक हैं और 2 लाख से ज्यादा स्नातक या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता पॉचवीं पास है।..... अगर दुनिया की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था में रोजगार का यह हाल है, तो विकास की परिभाषा पर हमें शक होना चाहिए। यह परिस्थिति कई समस्याओं पर लम्बे वक्त से ध्यान न देने की वजह से हुई है। एक बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा और रोजगार के बीच कोई तालमेल नहीं है। कई मामलों में लोग जितना पढ़ते जाते हैं, उतने ही रोजगार के लिए नाकाबिल होते जाते हैं।"[7]

भारत की उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा का लगातार गिरता स्तर देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पैदा कर रहा है जिससे हमारी शिक्षा प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बात को उजागर करते हुए रामदत्त त्रिपाठी नें लिखा है कि ''बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारी हमारी शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिह्न है। हमारी शिक्षा हमें हुनरमंद नहीं बनाती है। आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में जो विकास हुआ, उसमें भी युवकों के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए। जब लोगों के पास रोजगार और जेब में पैसा नहीं होगा, तो गोदाम में अनाज होते हुए भी लोग खाली पेट रहेंगे। भयंकर बेरोजगारी और गरीब–अमीर के बीच बढ़ती यह खाई असंतोष को जन्म दे रही है।"[8]

मुक्त बाजार तथा आर्थिक उदारीकरण नीति से भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था काफी प्रभावित हुयी है जिसके चलते स्ववित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था के तहत उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इससे पूँजीपतियों के लिए कालेधन के निवेश एवं मुनाफा खोरी का अवसर मिलता जा रहा है। उच्च शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश के निर्णय ने भारत में उच्च शिक्षा की विदेशी डिग्री बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। इन नीतियों से शिक्षा की समानता के अधिकार, शिक्षा सबका अधिकार जैसे लोक कल्याणकारी योजना को अमल मे लाने के बजाय सरकार ने उच्च शिक्षा को पूँजीपतियों के दुकानों के हवाले कर दिया है। इससे सरकारी व्यवस्था के तहत चलने वाले कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के प्रति

युवाओं का आकर्षण कम होता जा रहा है। उच्चशिक्षा के प्रति केन्द्र एवं राज्य सरकारों की बढ़ती उदासीनता के चलते ही शिक्षा एवं शोध के हर स्तर पर गिरावट जारी है। विश्वविद्यालयों द्वारा कराये जा रहे शोध केवल पीएचडी धारकों की संस्था बढ़ा रहे हैं। इन शोधों से समाज एवं देश का कोई भला होने वाले नहीं है। इसीलिए तो शोधों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देश की उच्च शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता में गिरावट के चलते ही भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची से लगातार बाहर ही थे किन्तु 16 सितम्बर 2015 को ''जारी क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2015–16 में आइ आइ एस सी बेंगलूरु को 147 और आइआइटी दिल्ली को 179वां स्थान मिला है।"[9] इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार एवं सर्वश्रेष्ठ बनने की नई आशा जगी है। देखना यह है कि भारत के अन्य विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान इससे कितनी प्रेरणा ग्रहण करके उच्च शिक्षा में गुणात्मक ह्रास को रोकने में सफल होते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथः–

1. गतिमान–2013, वी.बी.एस. पूर्वान्चल वि0 विद्यालय, जौनपुर, पृ0–22।
2. विलानिलम जे.वी.: भारत में शिक्षा व्यवस्थाः1947–2012, योजना, अगस्त 2012, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0–28।
3. चतुर्वेदी सीताराम,: आधुनिक भारत के निर्माता पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 1980, पृ0–67।
4. गुप्ता विशेषः शिक्षा और शोध की गुणवत्ता पर सवाल,समय live,03 अगस्त 2015
5. राजपूत जगमोहन सिंहः तलाशने होंगे सच्चे आयाम, दैनिक जागरण, वाराणसी, 21 दिसम्बर 2014, पृ0–11।
6. कुमार आनंदः तो युवा क्यों सपने पाले शिक्षक बनने के, दैनिक जागरण, वाराणसी, 21 दिसम्बर 2014, पृ0 –11।
7. सम्पादकीय, हिन्दुस्तान, वाराणसी, 18 सितम्बर 2015, पृ0–14।
8. त्रिपाठी रामदत्तः बढ़ती बेरोजगारी से चिन्ता,अमर उजाला,वाराणसी, 18 सितम्बर 2015, पृ0 –10।
9. दैनिक जागरण, वाराणसी, 16 सितम्बर 2014, पृ0–19।